उत्तर प्रदेश

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष

श्रीमती आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

का

अभिभाषण

लखनऊ, मंगलवार, 18 फरवरी, 2025 : माघ 29, शक सम्वत् 1946

उत्तर प्रदेश

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष

श्रीमती आनंदीबेन पटेल

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

का

अभिभाषण

लखनऊ, मंगलवार, 18 फरवरी, 2025 : माघ 29, शक सम्वत् 1946

माननीय सदस्यगण,

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को ईसवी सन् 2025 की शुभकामनाएँ। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व सम्पन्नता से परिपूर्ण हो।

मेरी सरकार को इस वर्ष दिव्य एवं भव्य महाकुम्भ आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महाकुम्भ–2025 में स्वच्छता, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था के नए मानक गढ़े गए हैं। महाकुम्भ में आस्था एवं आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। यह आयोजन जहाँ एक ओर अनेकता में एकता को दर्शाता है, वहीं दूसरी ओर समता व समरसता का संदेश भी दे रहा है, जिससे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा साकार हो रही है। अब तक लगभग 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुजन पावन त्रिवेणी में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हम सभी अत्यन्त दुःखी हैं। इसमें कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से कुछ श्रद्धालुओं की दुःखद मृत्यु भी हो गई। असमय काल–कवलित हुए ऐसे पुण्य आत्माओं के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि तथा उनके शोक संतप्त परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ।

अन्त्योदय से सर्वोदय मेरी सरकार का मंत्र है। समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े आर्थिक दृष्टि से सबसे कमजोर परिवारों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार ने गांधी जयन्ती के अवसर पर 02 अक्टूबर, 2024 से 'जीरो पॉवर्टी अभियान' की शुरुआत की है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के

प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार का यह भी प्रयास है कि इन परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, जिससे प्रतिवर्ष कम से कम रू0 1 लाख 25 हजार की आमदनी सतत् तरीके से हो सके। भारत सरकार में प्रस्तुत बजट वर्ष 2025–26 में विकसित भारत की परिकल्पना में भी जीरो पावर्टी को पहले स्थान पर रखा गया है।

मुझे आप सभी के समक्ष यह कहते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि **स्वामित्व योजना** के अंतर्गत पूरे देश में अब तक लगभग 02 करोड़ घरौनियाँ वितरित की गई हैं, जिसमें 90 हजार 573 ग्रामों के ड्रोन सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करते हुए एक करोड़ से अधिक ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) अकेले उत्तर प्रदेश में वितरित की गई हैं। ग्राम्य सशक्तिकरण की दिशा में मेरी सरकार की यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

मेरी सरकार द्वारा एक अभिनव पहल करते हुए राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उ0प्र0 स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम–2024 प्रख्यापित कर दिया गया है।

महाकुम्भ प्रयागराज 2025 के शुभ अवसर पर पावन त्रिवेणी तट पर 22 जनवरी, 2025 को मा0 मंत्रिपरिषद् की ऐतिहासिक बैठक भी आहूत की गई। इस बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

प्रदेश को वन ट्रिलियन यूएस डालर की अर्थव्यवस्था बनाये जाने का लक्ष्य पूर्ण किये जाने की दिशा में सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं। मेरी सरकार के सतत् प्रयासों के फलस्वरूप

08 वर्षों में प्रदेश को लगभग 45 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। इसके माध्यम से 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी तथा अन्य लाखों लोगों हेतु रोजगार का सृजन हुआ है। उत्तर प्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर भारत के विकास के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।

उत्तर प्रदेश, देश में एक्सप्रेस–वे प्रदेश के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित 04 बड़े एक्सप्रेस–वे (यमुना एक्सप्रेस–वे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे) संचालित हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश का सबसे लम्बा एक्सप्रेस–वे गंगा एक्सप्रेस–वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे निर्माणाधीन है। देश के कुल एक्सप्रेस–वे नेटवर्क में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक हिस्सेदारी है।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस–वे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे को पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस–वे, बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस–वे एवं आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे को वाया फर्रुखाबाद, गंगा एक्सप्रेस–वे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेस–वे तथा जेवर एयरपोर्ट लिंक एक्सप्रेस–वे के निर्माण हेतु कार्यवाही गतिमान है।

सरकार द्वारा प्रदेश के अन्दर कनेक्टिविटी को बढ़ाने तथा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए नए एक्सप्रेस–वे के निर्माण के लिए कार्यवाही संचालित हैः–

1. विंध्य एक्सप्रेस–वेः प्रयागराज–मीरजापुर–वाराणसी–चंदौली–सोनभद्र (320 किलोमीटर)।

2. चंदौली से गाजीपुर में पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस–वे को जोड़ने के लिए स्पर का निर्माण।
3. बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे को चित्रकूट से प्रयागराज होते हुए रीवा मार्ग से जोड़ने हेतु एक्सप्रेस–वे का निर्माण।
4. गंगा एक्सप्रेस–वे को मेरठ से हरिद्वार को जोड़ने हेतु एक्सप्रेस–वे का निर्माण।

डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के झाँसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, कानपुर नोड में अडानी डिफेंस सिस्टम एण्ड टेक्नोलॉजी, अलीगढ़ में एंकर रिसर्च लैब्स, लखनऊ में डी0आर0डी0ओ0 ब्रम्होस एयरोस्पेस सम्मिलित हैं, जिनमें लगभग 09 हजार 500 करोड़ का निवेश सम्भावित है।

सरकार द्वारा यमुना एक्सप्रेस–वे प्राधिकरण क्षेत्र में सेमीकण्डक्टर पार्क, डेटा सेन्टर पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। अन्य प्रमुख आगामी परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा निवेश क्षेत्र में एविएशन हब, एम0आर0ओ0–कार्गो कॉम्प्लेक्स, आगरा और प्रयागराज में इण्टीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर व हापुड़ में केमिकल और फार्मा पार्क जैसे सेक्टर विशिष्ट पार्क भी सम्मिलित हैं।

एवियेशन सेक्टर में जहाँ वर्ष 2017 से पूर्व मात्र 4 आपरेशनल एयरपोर्ट–लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एवं आगरा में थे, जो वर्तमान में बढ़कर 16 हो गये हैं।

वर्ष 2017 से अब तक जनपद कुशीनगर एवं अयोध्या में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण कार्य पूर्ण कर इन्हें संचालित किया जा रहा है। जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर में विश्वस्तरीय

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शीघ्र ही संचालन हो जाने से प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति में प्रभावी सुधार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में 20 घण्टा 35 मिनट, तहसील मुख्यालय पर 22 घण्टा 36 मिनट व जनपद मुख्यालय पर 24 घण्टे की आपूर्ति नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही है।

कानपुर में 3X660 मेगावॉट घाटमपुर तापीय परियोजना की प्रथम इकाई पूर्ण कर ली गयी है तथा द्वितीय एवं तृतीय इकाई से क्रमशः मई, 2025 एवं अगस्त, 2025 से उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा।

पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2017 से अब तक 24 हजार 800 करोड़ की लागत से 193 पारेषण उप केन्द्रों एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का ऊर्जीकरण किया गया है।

09 हजार 926 नये वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना तथा 28 हजार 602 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी पूर्ण किया गया है। किसानों के हित में 1 लाख 88 हजार निजी नलकूपों का संयोजन किया गया।

अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने का सरकार का विशेष लक्ष्य है, जिसमें अब तक 2 हजार 653 मेगावॉट क्षमता की सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएँ विकसित की जा चुकी हैं। इसी तरह प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भवनों पर 508 मेगावॉट क्षमता की सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना की गयी है।

सौर ऊर्जा नीति–2022 में 05 वर्षों में कुल 22 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बुन्देलखण्ड

क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरीडोर के अन्तर्गत 4 हजार मेगावॉट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है।

प्रदेश में लगभग 96 लाख एम0एस0एम0ई0 इकाईयों द्वारा 1 करोड़ 65 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए प्रदेश, देश में अग्रणी है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है, जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टीयुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के तहत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना का लक्ष्य है।

प्रदेश की एम0एस0एम0ई0 इकाइयों की बाजार तक सुलभ पहुंच के लिए प्रतिवर्ष उ0प्र0 इण्टरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। वर्ष 2024 में इस ट्रेड शो में देश–विदेश के 500 से अधिक ट्रेडर्स द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें रू0 2 हजार 200 करोड़ के आर्डर भी प्राप्त हुए।

प्रदेश में शहरी आबादी को गुणवत्तापरक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अन्तर्गत **अमृत योजना 2.0** में अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत लगभग 09 लाख व्यक्तिगत तथा 69 हजार से अधिक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराते हुए सभी नगरीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित कराने में सफलता प्राप्त की गयी है। विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से 1 हजार 100 ब्लॉक में सामुदायिक/सार्वजनिक/पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर आवंटित किये जा चुके हैं।

स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत सभी 17 नगर निगमों में 10 हजार 300 करोड़ से अधिक की 757 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 के गंगा टाउन कैटेगरी के अन्तर्गत नगर निगम, वाराणसी को प्रथम स्थान तथा प्रयागराज को द्वितीय स्थान के साथ–साथ नोएडा को स्टेट क्लीन सिटी का अवॉर्ड प्राप्त हुआ है।

नगरीय क्षेत्रों में पार्क एवं ओपेन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र बढ़ाने हेतु **'उपवन योजना'** लागू की गयी है।

उ0प्र0 राज्य राजधानी क्षेत्र का गठन करते हुए राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों को सम्मिलित कर उ0प्र0 स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम–2024 प्रख्यापित कर दिया गया है। आगामी 05 वर्षों में 100 नई टाउनशिप विकसित किये जाने का लक्ष्य है।

06 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध कराने के साथ उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक मेट्रो सेवा वाला राज्य है। कानपुर तथा आगरा में मेट्रो सेवा रिकॉर्ड समय में प्रारम्भ कर दी गयी है। देश की पहली आर0आर0टी0एस0 'नमो भारत' का संचालन भी उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ हो गया है।

कृषि विकास तथा किसान कल्याण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वर्ष 2016–2017 में खाद्यान्न उत्पादन मात्र लगभग 557 लाख मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर लगभग 669 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2016–17 में खाद्यान्न उत्पादकता

लगभग 27 कुन्तल प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर लगभग 31 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हो गयी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2024–25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 03 करोड़ कृषकों को लगभग 79 हजार 500 करोड़ रुपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उनके खातों में अन्तरित की गई है।

पी0एम0–कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में 22 हजार 89 सोलर पम्पों की स्थापना कराई गई है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु वर्ष 2024–25 में लगभग 66 लाख कुन्तल गुणवत्तापूर्ण बीजों का वितरण किया गया। श्री अन्न (ज्वार, बाजरा, कोदो, सावां, रागी/मडुआ आदि) के लगभग 2 लाख 50 हजार बीज मिनी किट निःशुल्क वितरित किए गए।

भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु वर्ष 2024–25 में लगभग 95 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण कृषकों को किया गया है, साथ ही लगभग 8 लाख 50 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये हैं।

राज्य सेक्टर से बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में 23 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गौ–आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है। केन्द्र पोषित नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फॉर्मिंग के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों में 94 हजार 300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

कृषकों को कृषि एवं सम्बद्ध विभागों की सभी सुविधाएं सुगमता से प्रदान करने के लिए प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री का कार्य अभियान के रूप में संचालित किया जा रहा है। अब तक लगभग 61 लाख फार्मर आई0डी0 निर्गत की जा चुकी हैं।

कृषकों को उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु प्रदेश की 125 मण्डियों में जनवरी, 2025 तक लगभग 06 हजार 99 करोड़ का डिजिटल व्यापार किया गया है। **ई–मण्डी योजना** के अंतर्गत इस अवधि में 06 हजार 922 ई–लाइसेंस निर्गत किये गये हैं और ई–मण्डियों में 04 करोड़ 18 लाख से अधिक ऑनलाइन पर्चियां निर्गत की गयी हैं।

मण्डी समितियों के माध्यम से कृषकों एवं व्यापारियों/आढ़तियों हेतु संचालित योजनाओं के तहत 2019–20 से वर्तमान तक 48 हजार 210 कृषक लाभार्थियों को लगभग 98 करोड़ 50 लाख के अनुदान की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

08 जनपदों में किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने की प्रक्रिया को और सरल बनाने हेतु 08 नयी मण्डी/उपमण्डी तथा लखनऊ में 49 करोड़ की लागत से किसान एग्रीमॉल का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है।

अमरोहा, वाराणसी एवं सहजनवा में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 88 ग्रामीण हाट बाजार भी पूर्ण कर लिये गये हैं।

कृषकों के हित के लिए एंड्रायड मोबाइल एप **यू0पी0 मण्डी भाव** का शुभारम्भ किया गया है, जिसमें कृषि बाजारों के बाजार भाव एवं मौसम की जानकारी प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है।

मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस को **'किसान सम्मान दिवस'** के रूप में मनाते हुए 23 दिसम्बर, 2024 को ट्रैक्टरों का वितरण कराया गया।

कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वर्ष 2017–18 के पूर्व यू0पी0 डास्प में केवल 01 योजना संचालित थी। वर्तमान में 05 नयी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

कृषकों की आय में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इंटरप्राईज़ेज ईको–सिस्टम स्ट्रेन्थेनिंग प्रोजेक्ट **यू0पी0 एग्री,** 04 हजार करोड़ रुपये की लागत से संचालित है।

जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रथम चरण पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश के 20 जनपदों में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी है। कुल 89 कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित हैं।

वर्ष 2016–17 में समस्त स्रोतों से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन 6 लाख 18 हजार मीट्रिक टन था जिसे वर्ष 2023–24 में दोगुना करते हुए लगभग 11 लाख 60 हजार मीट्रिक टन तक पहुँचाया गया।

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि तथा मत्स्य पालकों के कल्याण के लिए **प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना** व **निषादराज बोट सब्सिडी योजना** संचालित की जा रही है।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत जनपद गोरखपुर, झाँसी एवं चंदौली में नवीन मत्स्य मण्डी का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा हेतु अब तक कुल 1 हजार 551 बाढ़ परियोजनाएं पूर्ण करते हुए 32 लाख 87 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का बचाव करते हुए करोड़ों की आबादी को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2017 से अब तक लगभग 02 लाख 73 हजार करोड़ रुपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जा चुका है, जो वर्ष 1995 से मार्च, 2017 तक 22 वर्षों में हुए कुल भुगतान से भी 59 हजार 143 करोड़ रुपये अधिक है।

मार्च, 2017 से अब तक 03 नई चीनी मिलों की स्थापना, 06 चीनी मिलों का पुनर्संचालन तथा 38 चीनी मिलों का क्षमता विस्तार हुआ है, जिससे लगभग 1 लाख 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है। साथ ही, कुल 01 लाख 10 हजार 600 टी0सी0डी0 की अतिरिक्त पेराई क्षमता भी सृजित हुई।

विगत 07 वर्षों में प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल लगभग 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 30 लाख हेक्टेयर, गन्ना उत्पादकता लगभग 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 85 टन प्रति हेक्टेयर तथा चीनी मिलों की दैनिक गन्ना पेराई क्षमता 7 लाख 50 हजार टी0सी0डी0 से बढ़कर 8 लाख 50 हजार टी0सी0डी0 से अधिक हो गयी है।

प्रदेश में वर्ष 2017 तक एथेनॉल का कुल उत्पादन 42 करोड़ लीटर था, जो सत्र 2023–24 में बढ़कर 177 करोड़ लीटर हो गया है।

उत्तर प्रदेश प्रति वर्ष 600 लाख टन खाद्यान्न तथा 400 लाख टन फल एवं सब्जियों का उत्पादन करते हुए देश में प्रथम स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश से फल एवं सब्जियों के निर्यात की असीम सम्भावनाएं है। औद्यानिक उत्पादों का निर्यात किसानों की आमदनी में आशातीत बढ़ोत्तरी करेगा। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण से कार्गो प्लेन के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात का अवसर उपलब्ध होने वाला है।

उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक पशुधन आच्छादित राज्य है। गो–संरक्षण के लिये कुल 07 हजार 713 गौ–आश्रय स्थलों में लगभग 12 लाख 50 हजार गोवंश संरक्षित हैं। **मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना** तथा **पोषण मिशन** के तहत 01 लाख 05 हजार पशुपालकों को 01 लाख 63 हजार गोवंश सुपुर्द किये गये।

निराश्रित व छुट्टा गोवंशों से किसानों को मुक्ति दिलाने हेतु 352 निराश्रित वृहद गो–संरक्षण केन्द्र क्रियाशील किये गये हैं तथा 191 नये केन्द्रों का निर्माण पूर्ण होने की स्थिति में है।

पशुओं के स्वास्थ्य के दृष्टिगत वर्ष 2016–17 में 07 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में लगभग 14 करोड़ 50 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। लम्पी रोग से बचाव/नियंत्रण के लिये 01 करोड़ 92 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना (पशुपालन घटक) के अन्तर्गत मार्च 2024 तक कुल लगभग 05 लाख 60 हजार किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये।

उत्तर प्रदेश 412 लाख मी0टन दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से संबंधित कृषकों के लिए **मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना** एवं स्वदेशी नस्ल के

गोवंश हेतु **मुख्यमंत्री स्वदेशी गौवंश संवर्धन योजना** संचालित की जा रही है।

इसी तरह **नंदिनी कृषक समृद्धि योजना** के तहत दुग्ध उत्पादन तथा डेयरी की स्थापना के लिए लगभग 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है

जनपद बांदा में 20 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता का नया डेयरी प्लान्ट, जनपद वाराणसी में 20 मी0टन प्रतिदिन क्षमता के पाउडर प्लान्ट की स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा जनपद मेरठ में 04 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नवीन ग्रीन फील्ड डेयरी प्लान्ट पूर्ण होने की स्थिति में है।

जनपद झाँसी में स्थापित 10 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता के डेयरी प्लान्ट का 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता तक विस्तारीकरण एवं जनपद मथुरा में 30 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता (01 लाख लीटर प्रतिदिन विस्तारित क्षमता) का डेयरी प्लान्ट स्वीकृत किया गया है।

मनरेगा योजना के अंतर्गत मानव दिवस सृजन तथा धनराशि व्यय में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है, जिसमें महिलाओं की सहभागिता लगभग 42 प्रतिशत है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत 02 लाख 53 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 95 लाख से अधिक ग्रामीण परिवार की महिलाओं को 08 लाख

55 हजार 479 स्वयं सहायता समूहों, 53 हजार 685 ग्राम संगठनों एवं 02 हजार 945 संकुल स्तरीय संघों से आच्छादित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सर्वाधिक शौचालय निर्माण के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। लगभग 02 करोड़ 68 लाख ग्रामीण शौचालय निर्मित कर समस्त ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओ0डी0एफ0) घोषित किया गया है।

779 कॉमन सर्विस सेंटर एवं 23 हजार 916 पंचायत भवनों का निर्माण कराया गया है।

प्रथम बार जेम पोर्टल का इंटीग्रेशन भारत सरकार के साफ्टवेयर ई–ग्राम स्वराज्य से करते हुए ग्राम पंचायतों को ऑनलाइन क्रय प्रणाली से जोड़ दिया गया है।

ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्यों की पद पर रहते हुए मृत्यु की दशा में उनके परिवार/आश्रित के सहायतार्थ **पंचायत कल्याण कोष** की स्थापना की गई है जिससे अब तक कुल 2 हजार 22 आश्रितों/परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गयी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत लगभग 2 हजार 100 कि0मी0 लम्बाई के 365 मार्ग पूर्ण कराए गए हैं तथा लगभग 1 हजार 310 कि0मी0 लम्बाई के 297 मार्गों का निर्माण कार्य गतिमान है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए 09 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण एवं 11 किलोमीटर प्रतिदिन के औसत की दर से नव निर्माण कराया जा रहा है।

वर्ष 2017 के उपरान्त अब तक लगभग 32 हजार 74 किलोमीटर लम्बाई में मार्गो का नवनिर्माण तथा लगभग 25 हजार किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जा चुका है।

प्रदेश के 165 विकास खण्ड मुख्यालयों को 02 लेन सड़कों से जोड़ते हुए 01 हजार 385 किलोमीटर लम्बाई के 149 कार्य पूर्ण कराए गए हैं।

वर्ष 2024–25 के वित्तीय वर्ष में लगभग 40 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त तथा लगभग 16 हजार किलोमीटर लम्बाई के मार्गों का नवीनीकरण किया गया।

सिंगल यूज वेस्ट प्लास्टिक का उपयोग करते हुए लगभग 100 किलोमीटर लम्बाई के सड़क निर्माण के कार्य पूर्ण किए गए हैं।

जल जीवन मिशन **'हर घर जल'** कार्यक्रम के अन्तर्गत विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समस्त जनपदों के 2 करोड़ 67 लाख ग्रामीण परिवारों के सापेक्ष अब तक 2 करोड़ 34 लाख (87.53 प्रतिशत) परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान किया जा चुका है।

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 39 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही है एवं 28 परियोजनाएँ निर्माण के अन्तिम चरण में है।

लगभग 1 लाख 17 हजार स्कूलों एवं 1 लाख 56 हजार आँगनबाड़ी केन्द्रों को पाइप द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रदेश में 33 हजार 157 ग्रामीण पाइप पेयजल परियोजनाएँ सौर ऊर्जा आधारित बनाई गयी हैं जिन पर 900 मेगावॉट के सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं।

मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज–2, कनहर सिंचाई परियोजना, महराजगंज में रोहिन नदी पर रोहिन बैराज के निर्माण की परियोजनाएं प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 4 लाख 74 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 6 लाख 77 हजार कृषक लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' एवं **मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना** के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में 2 लाख 24 हजार 184 निःशुल्क बोरिंग, 2 हजार 397 गहरी बोरिंग व 4 हजार 574 मध्यम बोरिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 13 तालाब, 22 चेकडैम तथा 273 ब्लास्ट कूप का निर्माण किया गया है।

प्रदेश में संचालित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, राजकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त व समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों तथा सहायता प्राप्त मदरसों में कक्षा 01 से कक्षा 08 तक 1 करोड़ 49 लाख छात्र/छात्राओं को हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषा की पाठ्य–पुस्तकों के साथ दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि की पाठ्य–पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पी0एम0 श्री योजना के अन्तर्गत संचालित 1 हजार 565 विद्यालयों में आधुनिक अवस्थापना सुविधाएँ सुनिश्चित करते हुए आदर्श विद्यालय विकसित किये गये हैं।

कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराते हुए 680 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है।

बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत 06 हजार 481 जर्जर विद्यालयों का पुनर्निर्माण कराया जा चुका है।

छात्र–छात्राओं के लिये यूनीफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता–मोजा एवं स्टेशनरी हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से रुपये 1 हजार 200 प्रति बच्चे की दर से धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में दी जा रही है।

अनुश्रवण को प्रभावी बनाने हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ 02 लाख 10 हजार टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं।

कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के दृष्टिगत 18 हजार 381 परिषदीय उच्च प्राथमिक/कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास एवं 880 विद्यालयों में आई0सी0टी0 लैब की स्थापना की गयी है।

57 जनपदों में मुख्यमंत्री मॉडल कम्पोजिट विद्यालयों की स्थापना की जा रही है।

प्री–प्राइमरी एवं कक्षा 01 से कक्षा 08 तक के 377 परिषदीय विद्यालयों को **मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय** के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है।

वनटांगिया ग्रामों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से गोरखपुर एवं महराजगंज में 22 प्राथमिक एवं 11 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण किया गया है। महराजगंज के शेष 3 तथा गोण्डा के 2 वनटांगिया ग्रामों में विद्यालयों के निर्माण की कार्यवाही अंतिम चरण में है।

गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ की क्षमता को दोगुना किया जा रहा है। गोरखपुर में एन0सी0सी0 प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण भी पूर्ण होने की स्थिति में है।

मिशन रोजगार के अन्तर्गत अब तक 1 हजार 890 प्रवक्ता, 6 हजार 314 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है।

परम्परागत संस्कृत शिक्षा को रोजगार परक बनाने हेतु पौरोहित्य, वास्तुशास्त्र, योग विज्ञान में डिप्लोमा पाठयक्रम एवं छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है एवं 73 संस्कृत महाविद्यालयों को नवीन मान्यता प्रदान की गई है।

विन्ध्याचल धाम मण्डल में माँ विन्ध्यवासिनी विश्वविद्यालय, मिर्जापुर, मुरादाबाद मण्डल में गुरू जम्भेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद तथा देवीपाटन मण्डल में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, बलरामपुर की स्थापना की जा चुकी है।

कुशल प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के क्रम में प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

36 राजकीय पॉलीटेक्निक अवस्थापना की प्रक्रिया में पूर्ण होने की स्थिति में हैं। 89 पॉलीटेक्निकों में लैंग्वेज लैब एवं 251 स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना की जा चुकी है।

ए०के०टी०यू० द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अनुक्रम में हिन्दी में इंजीनियरिंग के कोर्स का संचालन प्रारम्भ है।

स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 02 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन निःशुल्क वितरित किये जाने के

लक्ष्य के सापेक्ष 49 लाख 86 हजार टैबलेट/स्मार्टफोन वितरित किये जा चुके हैं।

एच0बी0टी0यू0, कानपुर को नैक मूल्यांकन में **'ए प्लस' ग्रेड** तथा मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर को **'ए' ग्रेड** प्रदान किया गया है।

इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए रुपये 100 करोड़ की इनोवेशन निधि बनायी गयी है तथा 300 इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित होने की प्रक्रिया में है, जिनमें से 100 इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित किये जा चुके हैं।

2024–25 में 62 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

मेरी सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष तीन चरणों में एक माह का विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं 15 दिवसों का दस्तक अभियान संपादित किया जाता है।

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में ए0ई0एस0 रोगियों की संख्या में 85 प्रतिशत एवं ए0ई0एस0 रोगियों की मृत्यु की संख्या में 99 प्रतिशत की कमी हुई है। जे0ई0 के रोगियों की संख्या में 93 प्रतिशत एवं जे0ई0 रोगियों की मृत्यु में 98 प्रतिशत की कमी आयी है।

वर्ष 2017 की अपेक्षा वर्ष 2024 में डेंगू रोग से मृत्यु की दर में 94.5 प्रतिशत तथा मलेरिया के कुल मामलों में 56 प्रतिशत की कमी आयी है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से 01 करोड़ 80 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें

1 करोड़ 39 लाख परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व 49 लाख परिवार **मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान** से आच्छादित हैं।

आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है। आयुष्मान योजनान्तर्गत प्रदेश के कुल 5 हजार 834 चिकित्सालय सूचीबद्ध हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** के रूप में उच्चीकृत किये जाने का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में कुल 22 हजार 681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर पूर्ण होकर संचालित हो रहे हैं।

अब तक 181 मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले आयोजित हुए हैं, जिसमें लगभग 13 करोड़ 50 लाख रोगी लाभान्वित हुए।

प्रदेश में संचालित एम्बुलेंस सेवा की फ्लीट को 150 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रोगियों को चिकित्सा सेवाएं उनके द्वार पर ही उपलब्ध कराने हेतु 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना में आभा आई0डी0, हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर स्कैन एण्ड शेयर मॉडयूल, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में प्रदेश पूरे देश में अग्रणी राज्य की श्रेणी में आता है।

एक जनपद–एक मेडिकल कॉलेज की अवधारणा पूर्ण होने की स्थिति में है। वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज (44 राज्य सरकार एवं 36 निजी क्षेत्र) हैं तथा 59 जनपद मेडिकल कॉलेजों की सुविधा से आच्छादित हैं।

13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं जनपद महराजगंज, सम्भल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा जनपद मऊ में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है।

सरकारी मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में वर्ष 2017 में मात्र 1 हजार 990 एम0बी0बी0एस0 की सीटें थीं जिन्हें बढ़ाकर 5 हजार 250 किया है तथा निजी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सीटों की संख्या 2 हजार 550 को बढ़ाकर 6 हजार 550 किया गया है।

इसी तरह, पी0जी0 सीटों की संख्या वर्ष 2017 में 741 थी उसे बढ़ाकर 1 हजार 871 किया गया है और निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों में सीटों की संख्या जो 2017 में मात्र 480 थी उसे बढ़ाकर 2 हजार 100 किया गया है।

सरकारी मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशियलिटी सीटों की संख्या जो वर्ष 2017 में 120 थी, जिन्हें सत्र 2024–25 में बढ़ाकर 250 कर दिया गया है।

प्रदेश में स्वीकृत 27 नर्सिंग कॉलेजों में से 25 नर्सिंग कॉलेजों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है। एस0जी0पी0जी0आई0 में डायबिटीज सेन्टर की स्थापना की गयी है, इसके साथ ही 500 बेडेड एडवांस पीडियाट्रिक सेन्टर का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

एस0जी0पी0जी0आई0 में ही 08 नये विभाग प्रारम्भ किये गये हैं। आई0आई0टी0 कानपुर के अंतर्गत 500 शैय्यायुक्त सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय के साथ स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना की जा रही है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत निर्धन तथा मध्यम वर्ग के प्रतियोगी छात्रों को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2023–2024 में 22 लाख से अधिक छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवनयापन का अवसर प्रदान करने हेतु वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक लगभग 61 लाख वृद्धजनों को लाभान्वित किया गया है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत वर्ष 2023–2024 में लगभग 01 लाख 05 हजार जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है।

प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में जहाँ पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वितरित धनराशि लगभग 108 करोड़ रुपये थी वहीं 2024–25 में इस धनराशि को बढ़ाते हुए 300 करोड़ रुपये किया गया है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत 2016–17 में जहाँ केवल 984 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी थी वहीं माह दिसम्बर, 2024 तक 02 हजार 175 करोड़ रुपये वितरित करते हुए 01 लाख 60 हजार से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपये से माह दिसम्बर, 2024 तक 58 हजार 594 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक–युवतियों को 'ओ' लेवल एवं 'सी.सी.सी.' कम्प्यूटर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2016–17 में जहाँ प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 9 हजार 392 थी वह अब बढ़कर लगभग 22 हजार हो गयी है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल जैसी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2024–25 के आरम्भ में कुल 305 परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है तथा 216 परियोजनायें पूर्ण होने की स्थिति में हैं।

वर्ष 2017 के पूर्व दिव्यांगजन को केवल 300 रुपये प्रतिमाह प्रति दिव्यांग भरण पोषण अनुदान का भुगतान किया जा रहा था, उसे बढ़ाकर वर्तमान में रुपये 1 हजार करते हुए 11 लाख दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा चुका है।

महिलाओं एवं बच्चों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु **मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना** से अब तक 22 लाख 11 हजार लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।

निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र निराश्रित महिलाओं को प्रतिमाह रू0 1 हजार की पेंशन प्रदान करते हुए वर्ष 2016–17 में लगभग 17 लाख निराश्रित महिलाओं के सापेक्ष वर्ष 2023–24 में लगभग 34 लाख निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

आई0सी0डी0एस0 योजना के तहत 01 लाख 89 हजार 796 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित व क्रियाशील हैं।

अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत 06 माह से 06 वर्ष आयु तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार

का वितरण किया जाता है जिसका लाभ 2 करोड़ 12 लाख लाभार्थियों को देते हुए उनके जीवन में सुधार किया गया है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों के 14 से 18 आयु वर्ग की 2 लाख 10 हजार किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत रबी विपणन वर्ष 2024–25 में 01 लाख 80 हजार किसानों से गेहूं क्रय करते हुये 2 हजार 133 करोड़ 65 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

वर्ष 2024–25 में 5 लाख 97 हजार किसानों से धान क्रय करते हुये 9 हजार 423 करोड़ 41 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।

श्री अन्न के अन्तर्गत 306 व 79 क्रय केन्द्र स्थापित कर क्रमशः 1 लाख 1 हजार मीट्रिक टन बाजरा व 47 हजार मीट्रिक टन ज्वार की खरीद की गयी है।

भारत सरकार की **वन नेशन वन राशन कार्ड योजना** प्रदेश में मई, 2020 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अब तक अन्य राज्यों के 71 हजार 917 कार्ड धारकों को तथा उत्तर प्रदेश के 67 लाख 94 हजार कार्ड धारकों को खाद्यान्न प्रदान किया गया है।

वर्ष 2024–25 से **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** से आच्छादित लाभार्थियों को 02 सिलेण्डर रिफिल निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है।

राजस्व क्षेत्र में व्यापक सुरक्षा प्रदान किये जाने का शत–प्रतिशत सरकार का लक्ष्य है, जिसके तहत चार स्तरीय

एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स का गठन करते हुए 66 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराई गई। 142 अतिक्रमणकारियों को भू–माफिया के रूप में चिन्हित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की गई।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता की स्थिति में 5 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।

चकबन्दी एवं सर्वे से बाहर समस्त राजस्व ग्राम खतौनियों को डिजिटाइज कर ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसे तहसील एवं जन सेवा केन्द्रों पर प्राप्त किया जा सकता है।

सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत की कमी लाना सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को सुगम एवं सुचारु बनाने हेतु 53 जन सेवाओं को फेसलेस बनाया गया है जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन एवं फिटनेस आदि जन सेवायें उपलब्ध हैं।

रक्षाबन्धन पर्व पर वर्ष 2017 से वर्ष 2024 तक 01 करोड़ 20 लाख से अधिक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई गई।

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों के यात्रियों की मृत्यु होने पर दी जा रही राहत राशि रुपये 5 लाख को बढ़ाकर रुपये 07 लाख 50 हजार कर दिया गया है।

एक जनपद–एक खेल योजना के अंतर्गत प्रदेश के 72 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर संचालित हैं।

वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तथा सहारनपुर, फतेहपुर व बलिया तथा

वाराणसी के सिगरा में खेल स्टेडियम के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है।

गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का कार्य प्रगति पर है।

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करते हुए प्रदेश के 10 अन्तर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति प्रदान की गयी है और 479 कुशल खिलाड़ियों की पुलिस आरक्षी के पद पर भर्ती की गयी है। प्रदेश की शासकीय सेवाओं में खिलाड़ियों हेतु 02 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्राविधान किया गया है।

वर्ष 2024 में जनवरी से दिसम्बर तक 65 करोड़ से अधिक पर्यटक प्रदेश में आये, जिसमें 14 लाख विदेशी पर्यटक हैं।

वर्ष 2022 के बाद प्रदेश में 1 हजार से अधिक पंजीकृत पर्यटन इकाइयों द्वारा रुपये 23 हजार 452 करोड़ का निवेश किया जा रहा है, जिससे 03 करोड़ 72 लाख रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

जनपद अयोध्या में चौदह कोसी एवं चौरासी कोसी परिक्रमा मार्ग को आकर्षक एवं सुखद बनाये जाने हेतु पयर्टक सुविधाओं के विकास का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है।

जनपद कुशीनगर में **बुद्धा थीम पार्क परियोजना** का कार्य गतिमान है।

प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं तथा प्रदेश की विभिन्न अंचलों में बिखरी पड़ी सम्पदा के अवशेषों को संरक्षित करने का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। 60 वर्ष की

आयु पूर्ण कर चुके वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को रुपये 2 हजार की मासिक पेंशन दी जा रही है।

कौशाम्बी में संग्रहालय एवं बाराबंकी में पद्मश्री बाबू के0डी0 सिंह जी के पैतृक आवास को संग्रहालय, गोरखा रेजिमेन्ट सेन्टर, गोरखपुर में शहीद स्मारक एवं संग्रहालय तथा जनपद सुलतानपुर में नये भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर शहीदों की याद में सम्पूर्ण प्रदेश में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया।

भारतरत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर लखनऊ, बलरामपुर एवं बटेश्वर, आगरा में बृहद सांस्कृतिक आयोजन किये गये।

महाकुम्भ प्रयागराज–2025 में प्रदेश की प्राचीन कला, धरोहर एवं संस्कृति को डिजिटल माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

जनपद प्रयागराज में लगभग 23 करोड़ 09 लाख रुपये की लागत से **भजन संध्या स्थल** का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

अयोध्या में राम पथ, भक्ति पथ एवं जन्मभूमि पथ का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मीरजापुर में माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर व त्रिकोणी क्षेत्र के अन्य मन्दिरों के परिक्रमा मार्गों का सौन्दर्यीकरण लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है।

बंदियों को कुशल बनाने हेतु वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओ0डी0ओ0पी0) की तर्ज पर कारागारों में वन जेल वन प्रोडक्ट (ओ0जे0ओ0पी0) थीम अपनाई गई है।

प्रदेश के सभी 75 हजार होमगार्ड्स के ड्यूटी भत्ते में सम्मानजनक वृद्धि करते हुए पुलिसकर्मियों को प्राप्त न्यूनतम वेतन के बराबर ड्यूटी भत्ता किया गया है।

होमगाड्र्स स्वयंसेवकों की मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों के लिए रुपये 05 लाख की अनुग्रह राशि तथा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम के 30 लाख रुपये के बीमा का प्राविधान भी किया गया है। वर्ष 2024–25 में 538 मामलों में अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि एवं वानिकी में और प्रगति करते हुए वर्ष 2021–22 से वर्ष 2024–25 तक प्रदेश में लगभग 139 करोड़ पौधों का रोपण किया गया जिनका संरक्षण किया जा रहा है। इससे प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.96 प्रतिशत वनावरण व वृच्छादन का क्षेत्र हो गया है जो देश में द्वितीय स्थान पर है।

वर्ष 2014 के उपरान्त देश में प्रत्येक वर्ष 'संविधान दिवस' मनाया जा रहा है। संसदीय कार्य विभाग द्वारा संविधान के अमृत महोत्सव के अवसर पर दिनांक 26 नवम्बर, 2024 से दिनांक 26 नवम्बर, 2025 तक प्रदेश में संविधान के प्रति निष्ठा तथा कर्तव्य परायणता जागृत करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

इसी क्रम में महाकुंभ 2025 में संविधान गैलरी निर्मित की गयी है, जो लोगों के आकर्षण का केन्द्र है।

प्रयागराज में डा0 राजेन्द्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है एवं अस्थायी भवन में प्रथम शैक्षणिक सत्र का प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्ष 2024–25 में लोक अदालतों का आयोजन कर 02 करोड़ 91 लाख वाद निस्तारित किये गये एवं 5 हजार 800 विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया। वर्ष 2024

में 32 ग्राम न्यायालय क्रियाशील करते हुए वर्तमान में 100 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हैं।

प्रदेश के 10 जनपदों में **इन्टीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स** की स्थापना की जा रही है। इस हेतु रुपये 01 हजार 635 करोड़ से अधिक की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

गोरखपुर में महन्त अवेद्यनाथ ज्ञान–विज्ञान पार्क की स्थापना तथा वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के आधुनिकीकरण का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है। आगरा, बरेली एवं बांदा में साइंस सिटी की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में फसल गहनता, मोटे अनाज की फसलों एवं ऊसर भूमि संबंधी अध्ययन तथा प्रदेश में वर्ष 2024 में आयी बाढ़ से प्रभावित जनपदों का मानचित्रण किया गया।

उत्तर प्रदेश के निवासी 12 शहीद सैनिकों के आश्रितों को वर्ष 2024 में सेवायोजन प्रदान किया गया। प्रदेश के निवासी सैनिकों की वीर नारियों को रुपये 7 हजार 500 प्रतिमाह एवं उनके माता–पिता को रुपये 5 हजार प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है।

वर्ष 2017 के पश्चात् लखनऊ में अति विशिष्ट अतिथि गृह 'नैमिषारण्य' एवं नई दिल्ली के द्वारका में 'इन्द्रप्रस्थ' उत्तर प्रदेश अतिथि गृह का निर्माण कराकर संचालित किया जा रहा है। अयोध्या एवं प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है। राज्य अतिथि गृह 'गोमती' के नये भवन का निर्माण किया जा रहा है।

राज्य कर विभाग का प्रदेश के कुल कर राजस्व में 56 प्रतिशत का अंशदान है। वर्ष 2024–25 में दिसम्बर, 2024 तक रुपये 84 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत इस वर्ष 2024–25 में 200 लाभार्थियों को लगभग 20 करोड़ की धनराशि से लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2017 से पूर्व 05 वर्षों में खनन से मात्र 4 हजार 700 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष वर्ष 2017 से वर्ष 2024 के बीच 21 हजार 726 करोड़ रुपये का कुल राजस्व प्राप्त हुआ है। खनिज सेवाओं के ऑनलाइन निस्तारण हेतु इन्टीग्रेटेड यूनीफाइड इन्टरफेस 'यू0पी0 माइन मित्रा' पोर्टल विकसित किया गया है।

खनिजों के परिवहन की निगरानी हेतु महत्वपूर्ण मार्गों के 56 स्थानों पर ए0आई0 युक्त चेक गेट्स लगाये गये हैं। खनिजों के परिवहन प्रपत्रों की वैधानिकता की जांच से अब तक 450 करोड़ से अधिक राजस्व की वसूली की गयी है।

खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता एवं सर्विलांस की कार्यवाही करते हुए खाद्य नमूनों की जाँच की जा रही है। इस हेतु 36 सचल मोबाइल प्रयोगशालाएँ संचालित हैं।

प्रदेश में आगरा, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी, झाँसी व लखनऊ मण्डल में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाएं स्थापित हैं तथा शेष मण्डलों में प्रयोगशालाओं के निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है।

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से महिला स्वयं सहायता समूहों को **नमो ड्रोन दीदी योजना** के अन्तर्गत चयनित कर, किसानों के उपयोगार्थ नैनो यूरिया, नैनो डी0ए0पी0

एवं कृषि रक्षा रसायनों के छिड़काव हेतु किराए पर ड्रोन प्रदान करने के लिए उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरणों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण हेतु मानव सम्पदा पोर्टल क्रियाशील है। वर्ष 2024 में इस पोर्टल पर पंजीकृत समस्त 08 लाख से अधिक सेवा संबंधी मामलों को ऑनलाइन किया गया है।

इसी तरह राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजे जाने की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से **ई–अधियाचन पोर्टल** क्रियाशील है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत सेवा भर्ती बोर्ड, शिक्षा सेवा चयन आयोग, सहकारी सेवा मण्डल, पुलिस भर्ती बोर्ड को भी उक्त पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है।

मेरी सरकार द्वारा जनहित में परिवार के सदस्यों के पक्ष में अचल सम्पत्ति के अन्तरण हेतु दान विलेखों के पंजीयन पर स्टाम्प शुल्क 05 हजार रुपये तक सीमित कर दिया गया है।

बाबा साहब डॉ0 भीमराव आंबेडकर, लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल व अन्य महान विभूतियों के जन्मदिवस एवं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2023–24 में उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 13.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ रुपये 25 लाख 63 हजार करोड़ हो गया है।

प्रदेशवासियों को वर्तमान में कुल 20 हजार 416 बैंक शाखाओं, 04 लाख 932 बैंक मित्र एवं बी0सी0 सखी तथा 18 हजार 747 ए0टी0एम0 के माध्यम से सुगम बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राज्य कर्मियों की पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया को पूर्णतया ऑनलाइन कर दिया गया है।

युवाओं को सरकारी नीति निर्माण और क्रियान्वयन में सहभागिता प्रदान करने हेतु 108 आकांक्षात्मक विकास खण्डों में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा विकास खण्ड जमुनहा (श्रावस्ती) को प्रथम तथा कौशाम्बी को द्वितीय स्थान प्रदान किया गया है।

बुन्देलखण्ड के समृद्ध विकास हेतु बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु बांदा एवं झांसी के कृषि विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा कृषि केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झांसी में न्यूट्री सीरियल्स हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का कार्य पूर्ण होने की स्थिति में है।

प्रदेश के 08 जिलों में संचालित आकांक्षात्मक जनपद योजना की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रथम 10 जनपदों में उत्तर प्रदेश के 06 जनपद आये हैं, जिनमें बलरामपुर, सिद्धार्थनगर व सोनभद्र क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर तथा चन्दौली, फतेहपुर एवं बहराइच क्रमशः छठे, सातवें एवं नवें स्थान पर है।

चैम्पियन्स ऑफ चेन्ज पोर्टल आधारित रैकिंग में बलरामपुर को रुपये 20 करोड़ 41 लाख, बहराइच को रुपये 14 करोड़, चन्दौली को रुपये 38 करोड़ 66 लाख, चित्रकूट को रुपये 26 करोड़ 88 लाख, फतेहपुर को रुपये 31 करोड़ 42 लाख, सिद्धार्थनगर को रुपये 15 करोड़, सोनभद्र को रुपये 10 करोड़ 47 लाख एवं श्रावस्ती को रुपये 19 करोड़ 14 लाख की सहायता प्रदान की गयी है।

प्रदेश ने सतत् विकास लक्ष्य कार्यकम में सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एस0डी0जी0 इंडिया इंडेक्स 4.0 में फ्रंट–रनर श्रेणी प्राप्त की है। इसी तरह क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी में प्रदेश ने 100 स्कोर प्राप्त कर अचीवर की श्रेणी प्राप्त की है।

राशन कार्डधारक परिवारों (3 करोड़ 61 लाख परिवार) की राशन कार्ड संख्या ही उनकी फैमिली आई0डी0 है और जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं, उनकी फैमिली आई0डी0 बनाये जाने हेतु पोर्टल के माध्यम से 10 लाख 71 हजार 112 परिवारों की फैमिली आई0डी0 बनायी गयी है।

डी0बी0टी0 पोर्टल पर 31 विभागों की 201 योजनाओं को जोड़ा गया है। अब तक लगभग रुपये 01 हजार करोड़ की बचत हुई है।

औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024–25 में इन्वेस्ट यू0पी0 के अन्तर्गत इन्वेस्टर्स द्वारा आबकारी विभाग के साथ रुपये 38 हजार 142 करोड़ के 131 एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये गये हैं।

अल्कोहल निर्माण करने वाली इकाईयों द्वारा रुपये 02 हजार 296 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया गया है, जिनके एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं।

प्रदेश में अल्कोहल उत्पादन हेतु 93 आसवनियां स्थापित हैं, जिनसे नवम्बर, 2024 तक 217 करोड़ 45 लाख लीटर अल्कोहल का उत्पादन हुआ है। वर्ष 2024–25 में 73 करोड़ 28 लाख 77 हजार लीटर पावर अल्कोहल का उत्पादन किया गया है।

वर्ष 2023–24 में पेरे गये गन्ने से माह अक्टूबर, 2024 तक 494 लाख 50 हजार कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है।

समाज के लिए सुरक्षा उसकी मूलभूत आवश्यकता है। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और आमजन का शासन–प्रशासन से विश्वास उठ चुका था। पुलिस आधुनिकीकरण व सुधार करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया।

अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं पुलिसिंग के स्तर व गुणवत्ता में नियमित एवं समयबद्ध रूप से सुधार किये जा रहे हैं। प्रदेशवासियों को अपराधमुक्त एवं भयमुक्त वातावरण देकर रामराज्य की संकल्पना को साकार किया जा रहा है।

मेरी सरकार में अब तक कोई साम्प्रदायिक दंगा या जातिगत संघर्ष की घटना नहीं हुई है। विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहारों, मेलों, जुलूसों, शोभा यात्राओं व धार्मिक आयोजनों के साथ–साथ विभिन्न निर्वाचनों को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराये जाने में सफलता प्राप्त हुई है।

ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत जुलाई, 2023 से दिसम्बर, 2024 तक 51 अभियुक्तों को मृत्युदण्ड, 6 हजार 287 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 1 हजार 91 अभियुक्तों को 20 वर्ष से अधिक की सजा, 3 हजार 868 अभियुक्तों को 10 से 19 वर्ष तक की सजा, 5 हजार 788 अभियुक्तों को 05 से 09 वर्ष की सजा एवं 51 हजार 748 अभियुक्तों को 05 वर्ष से कम की सजा से दण्डित कराया गया है।

नवम्बर, 2019 से अब तक चिन्हित माफिया या गैंग के सदस्यों के विरुद्ध विचाराधीन मुकदमों की माननीय न्यायालयों में प्रभावी पैरवी करते हुए 31 माफिया व 74 सह–अपराधियों को अलग–अलग अभियोगों में आजीवन कारावास/कारावास व

अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया, जिसमें से 02 को मृत्युदण्ड की सजा हुई।

अवैध रूप से अर्जित बेनामी सम्पत्तियों को चिन्हित माफिया अपराधियों से मुक्त कराकर रुपये 4 हजार 74 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति का जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण एवं अवैध कब्जे से मुक्त कराते हुए रुपये 141 अरब से अधिक मूल्य की चल–अचल सम्पतियों को राज्य सरकार में निहित किया गया।

प्रदेश में भारतीय न्याय संहिता–2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता–2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम–2023 को 01 जुलाई, 2024 से सफलतापूर्वक लागू कर दिया गया है, जिसमें अब तक लगभग 02 लाख 50 हजार से अधिक मुकदमें पंजीकृत किए गए हैं।

महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तीकरण हेतु विभिन्न अभियान जैसे मिशन शक्ति–5.0, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन बचपन, ऑपरेशन खोज, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन रक्षा इत्यादि सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं।

ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सभी थानों में अब तक 11 लाख से अधिक सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित कर दिए गए हैं।

वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 में अभूतपूर्व सुधार करते हुए यू0पी0–112 का रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकेण्ड से घटाकर 07 मिनट 24 सेकेण्ड कर दिया गया है।

साइबर क्राइम की विवेचना हेतु वर्ष 2017 से पूर्व 02 थाने थे। वर्तमान सरकार द्वारा समस्त 75 जनपदों में साइबर क्राइम

थाने स्थापित करते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण किया जा रहा है।

ट्विटर पर प्राप्त शिकायतों को संज्ञान में लेकर वर्ष 2017 से अब तक 21 हजार 655 एफआईआर पंजीकृत किये गये हैं।

अपराधों को रोकने हेतु एस0टी0एफ0 द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 653 जघन्य अपराध घटित होने से पूर्व ही रोक लिये गये हैं।

ए0टी0एस0 द्वारा वर्ष 2017 से अब तक 130 आतंकवादी एवं 171 रोहिंग्या/बांग्लादेशी व सहयोगियों की गिरफ्तारी की गयी है।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा वर्ष 2017 के उपरान्त विभिन्न पदों पर 01 लाख 56 हजार से अधिक भर्ती की गई तथा 01 लाख 49 हजार से अधिक कर्मियों को प्रोन्नति प्रदान की गयी है। वर्तमान में अराजपत्रित श्रेणी के 92 हजार 919 पदों पर भर्ती हेतु कार्यवाही प्रचलित है।

मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों, प्रभावी कार्यान्वयन व सतत् अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश, देश में विभिन्न योजनाओं में **प्रथम स्थान** पर है :–

- मेरी सरकार के अथक प्रयासों से उत्तर प्रदेश धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों तथा पर्यटकों को आकर्षित करने में देश में शीर्ष स्थान पर है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) के अन्तर्गत आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 01 करोड़ 85 लाख निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
- पी0एम0 स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेण्डर्स को सर्वाधिक ऋण देकर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में स्वच्छ शौचालय निर्माण कर उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
- महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम।
- ईज ऑफ डुईंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश अचीवर्स स्टेट।
- 96 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 9 करोड़ 57 लाख खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 6 करोड़ 52 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 28 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ 12 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
- अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव–2024 में 25 लाख 12 हजार 585 दीप प्रज्ज्वलित कर पुनः गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज।

- कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना।
- तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
- गन्ना एवं चीनी, खाद्यान्न, आम, दुग्ध, आलू, शीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में लगातार प्रथम स्थान।
- देश में एथेनॉल के उत्पादन व आपूर्ति करने में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
- ई–मार्केट प्लेस (जेम) के अन्तर्गत सर्वाधिक सरकारी क्रय करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य बना।
- क्रेता–विक्रेता गौरव सम्मान समारोह–2023 में प्रदेश को 06 श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ।
- वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में इस वर्ष 36 करोड़ 51 लाख पौधों का रिकॉर्ड पौधरोपण।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ अंतर स्थलीय मात्स्यिकीय राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन की कार्ययोजना विकसित करने में देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी।
- कौशल विकास नीति को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य। एन0पी0एस0 ट्रेडर्स के अंतर्गत कामगारों का पंजीयन कराने में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर।

- भारत सरकार द्वारा आयोजित इण्डिया स्मार्ट सिटीज अवॉर्ड कॉन्टेस्ट–2022 में विभिन्न श्रेणियों में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित 9वीं स्मार्ट सिटी एक्सपो में कानपुर को पालिका स्पोर्ट स्टेडियम के आधुनिकीकरण व विकास कार्य हेतु बेस्ट हेरिटेज एण्ड हिस्टोरिक आर्किटेक्चर एण्ड लैण्ड मार्क प्रेजेन्टेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है।

माननीय सदस्यगण, वर्ष 2025 हम सभी के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है। इस वर्ष भारतीय संविधान ने 75 वर्षों की अपनी गौरवशाली यात्रा पूरी की है। इस अवसर पर मैं सभी संविधान शिल्पियों को नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारे पथ प्रदर्शन के लिए संविधान की रचना कर यह सुनिश्चित किया कि हमारी विकास यात्रा न्याय, समता और बन्धुता पर आधारित हो।

भारतीय गणतंत्र का यह अमृत वर्ष हमारे लिए संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने के साथ ही आजादी के अमृतकाल में एक सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में हमारे प्रयासों को और मजबूत करने वाला होगा।

गणतंत्र के अमृत वर्ष में सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। विगत 09 अगस्त 2024 से स्वाधीनता संग्राम के प्रेरक अध्याय काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। 2025 का यह वर्ष जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है।

मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख विकासोन्मुखी नीतियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। वित्तीय वर्ष 2025–2026 का आय–व्ययक शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। विगत सत्र के पश्चात् मैंने 02 अध्यादेश

पारित किये हैं, जिनके प्रतिस्थानी विधेयक व कतिपय अन्य महत्वपूर्ण विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यगण प्रदेश की आम जनता के व्यापक हित में मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे व इस सदन की उच्च गरिमा व पवित्रता बनाये रखेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके स्वस्थ एवं सुखद जीवन की मंगल कामना करते हुए आपको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने मध्य आने और सरकार के कार्य–कलापों को प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया।

जयहिन्द।